

सत्रह राज्यों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश के विभिन्न राज्यों में पिछले दो दिनों से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। मौसम विभाग ने मंगलवार को पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के 16 राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें बिहार, झारखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं।

उत्तरी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मार्च माह में हो रही बर्फबारी से ठंड का असर फिर बढ़ गया है। बर्फबारी के कारण गुरेज-बांदीपोरा मार्ग, सिंधन-किश्तवाड़ मार्ग और मुगल मार्ग बंद कर दिए गए हैं, वहीं जोजिला दर्रे पर बर्फ जमने से श्रीनगर-लेह राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम का मंदिर परिसर बर्फ की मोटी चादर से ढंक गया है। केंदारनाथ में तापमान शून्य से 11 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री में भी लगातार हिमपात हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। मैदानी इलाकों में भी मौसम का



पहाड़ों में बर्फबारी से लौटी ठंड, मध्य भारत में बढ़ेगा तापमान

असर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और बिजनौर में तेज आंधी और बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। सहारनपुर में आंधी के कारण टिन शेड गिरने से दो लोगों की मृत्यु हो गई। झारखंड,

छत्तीसगढ़ और बिहार में भी कई स्थानों पर बारिश और तेज हवाएं चलीं। हालांकि मौसम विभाग ने मध्य भारत के क्षेत्रों, जैसे दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और गुजरात में किसी विशेष चेतावनी की घोषणा

नहीं की है। यहां एक बार फिर तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई है। आगामी दो दिनों के लिए भी मौसम में बदलाव के संकेत हैं। 18 मार्च को छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

में कुछ स्थानों पर गरज के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में तेज हवाओं के साथ आंधी चलने की संभावना है। 19 मार्च को हिमाचल

प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में गरज-चमक के साथ ओले गिर सकते हैं। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अयोध्या-मथुरा दौरा

संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करेंगी

नईदुनिया ब्यूरो, मथुरा: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 21 मार्च तक उत्तर प्रदेश के अयोध्या और मथुरा में तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगी। अयोध्या में वह श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन और पूजन के साथ श्रीरामयंत्र की स्थापना करेंगी। इस यंत्र का वजन लगभग 150 किलोग्राम है और इसमें सोने की परत चढ़ी है। यह यंत्र कांचीपुरम मठ के प्राचीन यंत्र के आधार पर बनाया गया है और इसे भव्य रथयात्रा के माध्यम से अयोध्या लाया गया था।

राष्ट्रपति मुर्मू अयोध्या से मथुरा पहुंचेंगी और सबसे पहले इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण, बलराम, राधा-कृष्ण और नितार्ई गौर के दर्शन करेंगी। इसके बाद प्रेम मंदिर जाएंगी, जहाँ जगद्गुरु कृपालु महाराज द्वारा बनाए गए मंदिर में भगवान कृष्ण की आरती में शामिल होंगी।

दूसरे दिन राष्ट्रपति सुबह 7:25 बजे केली कुंज आश्रम पहुंचेंगी और संत प्रेमानंद महाराज से आध्यात्मिक चर्चा करेंगी। संत प्रेमानंद महाराज राधारानी की भक्ति में लीन हैं और उनके शिष्यों में क्रिकेटर विराट कोहली और



अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी शामिल हैं। राष्ट्रपति इसके बाद बाबा नीब करौरी के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। बाबा नीब करौरी ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपना शरीर त्यागा था। इसके बाद राष्ट्रपति उड़िया बाबा के समाधि स्थल पर दर्शन करेंगी। उड़िया बाबा का जन्म ओडिशा में हुआ था और राष्ट्रपति भी ओडिशा की रहने वाली हैं, इसलिए उनका आध्यात्मिक संबंध अधिक गहरा है। राष्ट्रपति का यह दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

शी जिनपिंग की किताब जलाने का विवाद चीन ने जताई नाराजगी, नेपाल सरकार को नोट भेजा

काठमांडू, एप्रैल 18: नेपाल के मोरंग जिले के मनमोहन टेंकिनकल कॉलेज में शनिवार रात सैकड़ों किताबें जलाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लिखी किताब 'चीन की शासन व्यवस्था' की कई प्रतियां भी शामिल थीं।

चीन ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है। काठमांडू स्थित चीनी दूतावास ने नेपाल के विदेश मंत्रालय को औपचारिक नोट भेजकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। नेपाल के गृह मंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने कहा कि जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुष्टि की कि चीन ने इस मामले पर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। चायरल वीडियो के बाद मोरंग के मुख्य जिला अधिकारी युवराज कट्टेल ने



मोडिया से वीडियो हटाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे नेपाल-चीन संबंधों पर असर पड़ सकता है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि ये किताबें कई सालों से बेकार पड़ी थीं और उनमें कोई लाना गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि स्थान खाली करने के लिए यह किया गया। हालांकि पत्रकारों ने बताया कि कई किताबें नहीं जैसी हालत में

थीं। चीन पहले से ही नेपाल में कुछ मुद्दों को लेकर चिंतित था। इनमें तिब्बती धार्मिक नेताओं की यात्रा, पोखरा हवाई अड्डे से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले और 5त नेटवर्क में चीनी कंपनी हुवावे की भूमिका शामिल हैं। सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने दावा किया कि हजारां किताबें जलाई गईं और सवाल उठाया कि इतनी किताबें कहाँ से आईं।

ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर अमेरिकी मीडिया में दावा जासूसी सूत्रों के अनुसार संभवतः समलैंगिक संबंध

वॉशिंगटन, एप्रैल 18: अमेरिकी राष्ट्रपति को पिछले सप्ताह एक सीक्रेट ब्रीफिंग दी गई थी, जिसमें ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई के समलैंगिक होने की आशंका जताई गई। यह जानकारी अमेरिकी अखबार ने प्रकाशित की है। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी जासूसी एजेंसियों ने बताया कि मुजतबा का बचपन के एक शिक्षक के साथ लंबे समय तक संबंध रहा। कुछ सूत्रों का कहना है कि उनके परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति के साथ भी उनके संबंध थे। जब यह ब्रीफिंग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी गई, तो वे हैरान हुए और जोर से हंस पड़े। कमरे में मौजूद अन्य अधिकारी भी इसे मजेदार मानकर हंस पड़े। अमेरिकी अखबार ने इस रिपोर्ट के लिए तीन सूत्रों का हवाला दिया है,



जिनमें दो इंटरलिजेंस अधिकारी और एक व्हाइट हाउस का करीबी व्यक्ति शामिल हैं। हालांकि,

अमेरिका के पास इस दावे को प्रमाणित करने वाला कोई फोटो या वीडियो सबूत नहीं है। ईरान में

समलैंगिक संबंध गैरकानूनी हैं और इसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान भी है। इस प्रकार के

आरोप न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक विवाद भी उत्पन्न कर सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार मुजतबा खामेनेई के पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई को यह डर था कि उनके बेटे की इस पहचान के कारण देश को सुचारु रूप से चलाना कठिन हो सकता है। यह जानकारी अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संवेदनशील और विवादस्पद मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की रिपोर्ट से ईरान-अमेरिका संबंधों में तनाव और बढ़ सकता है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर परिणाम भी सामने आ सकते हैं। इस घटना ने वैश्विक मीडिया और कूटनीतिक पटल पर चर्चा को जन्म दिया है।

अब गुजरात में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी तेज



मार्च को विधानसभा में रखा जाएगा और 24 मार्च को विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, जो वर्तमान बजट सत्र का अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जानकारी दी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने विस्तृत अध्ययन के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। रिपोर्ट में विवाह, तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे विषयों पर सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया है।

इस प्रारूप में महिलाओं के समान अधिकार और उनकी सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, गुजरात की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए संतुलित प्रावधान शामिल किए गए हैं।

समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपी अंतिम रिपोर्ट सेवानिवृत्त अधिकारियों ने राहुल को लिखा पत्र

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों, पूर्व पुलिस अधिकारियों और पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों सहित कुल 204 लोगों ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर संसद परिसर में किए गए विरोध को अनुचित बताया है। पत्र में उनसे देश से माफी मांगने की अपील की गई है। पत्र में कहा गया है कि 12 मार्च को संसद परिसर में किया गया विरोध संसदीय नियमों और गरिमा के विपरीत था। इससे पहले भी स्पीकर द्वारा परिसर में प्रदर्शन न करने के निर्देश दिए जा चुके थे, इसके बावजूद विरोध किया गया। पूर्व अधिकारियों ने कहा कि राहुल गांधी कुछ सांसदों के साथ संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय और बिस्कुट लेते हुए विरोध करते दिखाई दिए, जो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि सांसदों की सीढ़ियों पर प्रदर्शन का स्थान नहीं है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि संसद लोकतंत्र का प्रमुख केंद्र है और उसकी मर्यादा हर स्थान पर बनी रहनी चाहिए। सीढ़ियां, गलियारे और अन्य हिस्से भी उसी संस्था का भाग हैं, इसलिए वहां आचरण अनुशासित होना आवश्यक है। यह पत्र जम्मू-कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक एस.पी. वैद द्वारा जारी किया गया है, जिस पर 116 सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, 84 पूर्व प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्य हस्ताक्षरकर्ता शामिल हैं।

‘सरके चुनर’ गाना यूट्यूब से हटाया गया

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनोट ने नोरा फतेही और संजय दत्त पर फिल्माए गए गाने ‘सरके चुनर तेरी सरके’ को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड अश्लीलता की सारी हदें पार कर चुका है और ऐसे कंटेंट पर सखती जरूरी है।

यह गाना फिल्म ‘केडी: द डेविल’ का है। रिलीज के तुरंत बाद इसके बोल और विजुअल्स को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे वल्गार और अशोभनीय बताया। बढ़ते विरोध के बीच गाने को यूट्यूब और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों से हटा दिया गया।

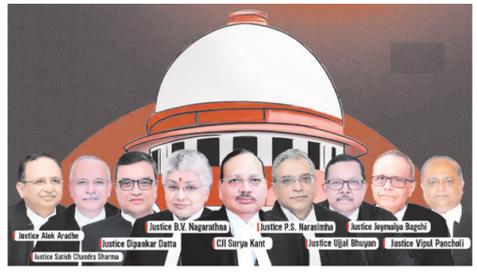
वकील विनीत जंदल ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने गाने को अत्यधिक अश्लील और यौन संकेतों से भरा बताया। मामले ने तूल पकड़ने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी सजा न लेते हुए नोटिस जारी किया।

‘उद्योग’ की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट को नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मंगलवार को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में ‘उद्योग’ शब्द की परिभाषा से जुड़े महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई शुरू की।

इस सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि सरकारी विभाग, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और गैर-लाभकारी संस्थाएं ‘उद्योग’ की श्रेणी में आएंगी या नहीं तथा उन पर श्रम कानून लागू होंगे या नहीं।

पीठ की अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे हैं। अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति उज्वल भुइयां, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची, न्यायमूर्ति आलोक अराधे और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली शामिल हैं। सुनवाई के दौरान पक्षकारों ने



वर्ष 1978 के ‘बैंगलोर वाटर सप्लाय एंड सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा’ मामले में दी गई ‘उद्योग’ की परिभाषा पर प्रारंभिक दलीलें प्रस्तुत कीं। उस फैसले में व्यापक परिभाषा दी गई थी, जिसके अनुसार जहां नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध हो और कोई सेवा प्रदान की जा रही हो, उसे उद्योग माना जा सकता है। इसी परिभाषा के कारण सरकारी विभाग, अस्पताल, विद्यालय और गैर-लाभकारी संस्थाएं भी उद्योग की श्रेणी में

शामिल मानी जाने लगीं और उन पर श्रम कानून लागू होने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट यह विचार कर रहा है कि इस परिभाषा को यथावत रखा जाए या इसके दायरे को सीमित किया जाए।

इस मामले में यह भी तय होगा कि सरकार के कौन-कौन से कार्य, जैसे पुलिस और रक्षा, उद्योग की परिभाषा से बाहर रहेंगे। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या केवल स्पष्ट नियोक्ता-कर्मचारी संबंध वाली संस्थाओं को ही उद्योग माना जाए।

ओडिशा में कांग्रेस के तीन विधायक निष्कासित

नईदुनिया ब्यूरो, भुवनेश्वर/चंडीगढ़: ओडिशा में कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले तीन विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने इन विधायकों को विधानसभा से अयोग्य घोषित करने के लिए स्पीकर को पत्र भी भेजा है। निष्कासित विधायकों में रमेश जेना, दशरथी गोमांगो और सोफिया फिस्टौस शामिल हैं। इन तीनों ने भारतीय जनता पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय के पक्ष में मतदान किया था। इसके चलते कांग्रेस और बीजू जनता दल के संयुक्त उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। वहीं हरियाणा में कांग्रेस पांच विधायकों को नोटिस देने की तैयारी कर रही है। इसी बीच हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिससे संपादन को झटका लगा है। दोनों राज्यों में कांग्रेस के कुल 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। 16 मार्च को आठ सीटों पर हुए चुनाव में नौ सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खाते में गईं।

स्पेशल खबर जज, वकील और पुलिस यूनिफॉर्म में न आएँ, बच्चों का मनोवैज्ञानिक डर कम होगा

फैमिली कोर्ट में बच्चों के लिए बदलाव का सुझाव

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि फैमिली कोर्ट में बच्चों के मनोवैज्ञानिक डर को दूर करने के लिए कोर्ट के पारंपरिक कामकाज में बदलाव किए जाने चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या फैमिली कोर्ट में काले चोगे और वर्दी पहनकर जज, वकील और पुलिस अधिकारी उपस्थित होने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के मन में डर पैदा होता है।

सोर्साइ ने सुझाव दिया कि फैमिली कोर्ट में पीटासीन जज और वकील यूनिफॉर्म में न आएँ और पुलिस अधिकारी भी वर्दी में



उपस्थित न हों। उनका मानना है कि फैमिली कोर्ट का उद्देश्य परिवारों के भीतर के विवादों को सुलझाना और मानवीय रिश्तों को

सुधारना है। सोर्साइ ने चार मुख्य बिंदु बताए। उन्होंने कहा कि फैमिली कोर्ट के मामलों में पारिवारिक विवाद, भावनात्मक

और सामाजिक परिणाम शामिल होते हैं, इसलिए इसे अन्य कोर्ट की तरह गंभीर और डराने वाला नहीं होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इसे ‘पारिवारिक समाधान केंद्र’ कहा जा सकता है। कार्यक्रम में दिल्ली के रोहिणी में फैमिली कोर्ट की आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय सहित सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज भी उपस्थित थे। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि जिला कोर्ट को बजट, कर्मचारी और जगह जैसी

चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सोर्साइ ने कहा कि फैमिली कोर्ट में सुधार का मकसद बच्चों और परिवारों के लिए एक सुरक्षित और डर-मुक्त वातावरण तैयार करना है। उनका मानना है कि पारिवारिक विवादों को सुलझाने में न्यायालय का स्वरूप मित्रवत और सहयोगात्मक होना चाहिए, जिससे बच्चों और परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। फैमिली कोर्ट में यह बदलाव बच्चों के हित और पारिवारिक मामलों के समाधान के लिए अहम कदम माना जा रहा है।

लंदन में हलाल मीट विवाद सिख रेस्टोरेंट मालिक और पाकिस्तानी समुदाय में टकराव

नईदुनिया ब्यूरो, जालंधर: लंदन के हाई-प्रोफाइल इलाके हेमरिस्मिथ में पंजाबी रेस्टोरेंट मालिक हरमन कपूर और पाकिस्तानियों के बीच हलाल मीट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। 16 साल से रेस्टोरेंट चला रहे हरमन कपूर ने कहा कि हलाल मीट बेचने से मना करने पर पाकिस्तानियों के 100 लोगों के समूह ने हमला किया। विवाद 14 मार्च को शुरू हुआ, जब हरमन कपूर ने रेस्टोरेंट पर बोर्ड लगाया कि उनके रेस्टोरेंट में हलाल मीट उपलब्ध नहीं होगा। पोस्टर लगाने के बाद पाकिस्तानियों की भीड़ जमा हो गई और तोड़फोड़ की कोशिश की। हरमन ने अपना सुरक्षा के लिए गारता दिखाया। हमले के बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हरमन कपूर को ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि गारता दिखाणा कानूनी अपराध है। बाद में बेल मिलने पर हरमन कपूर रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर घटना की जानकारी देते दिखे।